



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]  
No. 424]नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2006/वैशाख 8, 1928  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2006/VAISAKHA 8, 1928

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2006

का. आ. 625(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश

श्री अनुभव आनन्द अरोन, अधिवक्ता, निवासी, जी-1, 141, मदनगीर, नई दिल्ली, द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा, आसीन लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरहता के संबंध में तारीख 20 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 29 मार्च, 2006 के एक निर्देश द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन लोकसभा के सदस्य बने रहने के लिए निर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपांध द्वारा) दे दी है कि सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा की अभिकथित निरहता का प्रश्न जो एकदम निर्वाचन - पूर्व निरहता का मापला है, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है या राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चय नहीं किया जा सकता है और यह कि वर्तमान याचिका राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री अनुभव आनन्द अरोन, अधिवक्ता, की याचिका चलने योग्य नहीं है।

भारत का राष्ट्रपति

27 अप्रैल, 2006

[फा. सं. एच-11026(5)/2006-वि. II]

एन. के. नम्पूतिरी, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी  
उपाधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन  
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2006 का निर्देश मामला सं. 13

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश: संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा, आसीन लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरहता ।

#### राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 29 मार्च, 2006 का निर्देश है जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा आसीन लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरहता के प्रश्न के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।

2. उपरोक्त प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) के खंड (क) के अधीन लोकसभा का सदस्य बने रहने के लिए वर्ष 2004 में लोकसभा के लिए कराए गए साधारण निर्वाचन में लोकसभा के लिए निर्णायित प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा की अभिकथित निरहता के प्रश्न को उतारे हुए संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को श्री अनुभव आनन्द अरोन, अधिवक्ता, निवासी, जी-1, 141 मदनगीर, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई तारीख 20 मार्च, 2006 की याचिका में इस आधार पर उठाया गया था कि वह जुलाई, 2002 से जुलाई, 2004 तक अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष का पद धारण किए हुए था । अपनी याचिका में याची के कथन के अनुसार प्रो० मल्होत्रा को जुलाई, 2002 में अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

था और जिस समय प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा ने वर्ष 2004 में लोकसभा का साधारण निर्वाचन लड़ा था उस समय वह उक्त पद धारण किए हुए था। इसके अतिरिक्त याची ने यह कथन किया है कि प्रो० मल्होत्रा ने तारीख 15 जुलाई, 2004 को उक्त परिषद् के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। इस प्रकार याचिका में ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं है कि प्रो० मल्होत्रा को वर्ष 2004 में लोकसभा के लिए उसके निर्वाचन के पश्चात् किसी समय इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।

3. यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन संसद के आसीन सदस्य की निरहता के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरहताओं में ही उत्पन्न होती है। अभिकथित निरहता के ऐसे प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर केवल पश्च-निर्वाचन निरहता के मामले में भी उत्पन्न होती है। निर्वाचन - पूर्व निरहता, अर्थात् ऐसी निरहता का कोई प्रश्न जिससे कोई व्यक्ति उसके निर्वाचन के समय या निर्वाचन से पूर्व ग्रस्त था, केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग-6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के उपबंध के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के द्वारा ही उठाया जा सकता है और न कि किसी अन्य रीति से। इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201) ; बृंदाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609) ; आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की शृंखला निर्देश का उल्लेख किया जाता है। पूर्व में अन्य इसी प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और सचियों के राज्यपालों द्वारा आयोग को किए गए निर्देशों के संबंध में इसी प्रकार की राय दी है।

4. उपरोक्त निर्दिष्ट सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा की अभिकथित निरहता के प्रश्न को जो यदि कोई मामला है तो निर्वाचन - पूर्व निरहता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अभिकथित पूर्व-निर्वाचन निरहता के प्रश्न के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त करने की भी कोई अधिकारिता नहीं है। अतः, वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निवधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है।

5. तदनुसार वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त आशय की इस राय के साथ वापस भेजा जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन चलने योग्य नहीं है।

(नवीन बी. चावला)  
निर्वाचन आयुक्त

(बी.बी. टंडन)  
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

(एन. गोपालस्वामी)  
निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली:

तारीख: 7 अप्रैल, 2006

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2006

**S. O. 625(E).**—The following Order made by the President is published for general information:—

**ORDER**

Whereas a petition dated the 20<sup>th</sup> March, 2006 of alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra, a sitting Member of Lok Sabha under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Anubhav Anand Aron, Advocate, Resident of G-1<sup>st</sup>, 141, Madangir, New Delhi;

And whereas the President, by a reference dated the 29<sup>th</sup> March, 2006, under clause (2) of article 103 of the Constitution, has sought the opinion of the Election Commission on the question as to whether Prof. Vijay Kumar Malhotra had become subject to disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that in view of the well settled constitutional position, the question of the alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra, being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised before, or decided by, the President under clause (1) of article 103 of the Constitution and that the present petition is, therefore, not maintainable before the President;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the petition of Shri Anubhav Anand Aron, Advocate, is not maintainable.

**PRESIDENT OF INDIA**

27th April, 2006

[F. No. H-11026(5)/2006-Leg. II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. &amp; Legislative Counsel

**ANNEX****ELECTION COMMISSION OF INDIA****Reference Case No. 13 of 2006**

[Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India]

In re: Alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra, a sitting member of Lok Sabha, under Article 102(1)(a)) of the Constitution of India.

### OPINION

This is a reference dated 29<sup>th</sup> March, 2006, from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra, a sitting member of Lok Sabha, under Article 102(1)(a) of the Constitution of India.

2. The above question arose on the petition dated 20<sup>th</sup> March, 2006, submitted by Shri Anubhav Anand Aron, Advocate, R/o G-1<sup>st</sup>, 141 Madangir, New Delhi, to the President of India, under Article 103(1) of the Constitution, raising the question of alleged disqualification of Prof. Malhotra, elected to the Lok Sabha at the general election held to the Lok Sabha in 2004, for being a member of Lok Sabha, under clause (a) of Article 102(1) of the Constitution of India, on the ground that he was holding the office of President of All India Council for Sports, from July 2002 to July, 2004. As per the statement of the petitioner in his petition, Prof. Malhotra was appointed as the President of the All India Council for Sports in July, 2002, and he contested the general election to the Lok Sabha in 2004 while he was holding the said office. The petitioner has further stated that Prof. Malhotra resigned from the office of the President of the said Council on 15<sup>th</sup> July, 2004. Thus, the petition does not contain any allegation, whatsoever, that Prof. Malhotra was appointed to this post at any point of time after his election to the Lok Sabha in 2004.

3. It is well settled that under Article 103(1) of the Constitution of India, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting member of Parliament arises only in disqualifications incurred after election as a member of the House. The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of the alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103(2) of the

Constitution, also arises only in case of post-election disqualification. Any question of pre-election disqualification, i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to his election, can be raised only by means of an election petition presented in accordance with the provision of Art. 329(b) of the Constitution read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951, and in no other manner. Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (ARI 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609); etc. In a very large number of other similar cases in the past, the Commission has given similar opinion, on the references made to it by the President and Governors of States.

4. In view of the well settled constitutional position, referred to above, the question of the alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra, being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised under Article 103(1) of the Constitution. The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. The present petition is, therefore, not maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution.

5. The reference received from the President, in the present case, is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that it is not maintainable under Article 103(1) of the Constitution.

Navin B.Chawla  
(Navin B.Chawla)

Election Commissioner  
New Delhi.

Dated : 7<sup>th</sup> April, 2006.

B.B.Tandon  
(B.B.Tandon)

Chief Election Commissioner

N.Gopalaswami  
(N.Gopalaswami)

Election Commissioner